



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]  
No. 283]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2017/आषाढ़ 22, 1939  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2017/ASADHA 22, 1939

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 जून, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2017

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/011.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में,—
  - (i) विनियम 2 में,—

(क) खंड (कक) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“(कक) “सहयुक्त” (सहयोगी/असोसिएट) से ऐसी कोई एंटीटी अभिप्रेत होगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (6) के अधीन या लागू लेखा मानकों (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) अधीन सहयुक्त (सहयोगी/असोसिएट) हो और जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल होगा जिसका निदेशक, यथास्थिति, डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) का भी निदेशक हो;”;

(ख) खंड (कख) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“(कख) “निगमित निकाय” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (11) में या के अधीन इसके लिए नियत है और इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, इसमें शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (72) के अधीन यथा परिभाषित लोक वित्तीय संस्था, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, केन्द्र या राज्य की किसी विधि के अधीन स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जिसकी ऋण प्रतिभूतियाँ (डेट सिक्यूरिटीज़) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 [सेबी (इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्यूरिटीज़) रेग्यूलेशन, 2008] के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों या जो अपनी ऋण प्रतिभूतियाँ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराना चाहे, या बोर्ड द्वारा जारी किसी विनियम के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों का कोई अन्य निर्गमकर्ता (इश्युअर);”;

(ग) खंड (कड) में, खंड (i) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“(i) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्विज़ीशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन, 2011] के विनियम 4 के प्रावधानों (उपबंधों) के अनुसार नियंत्रण में परिवर्तन;”;

(घ) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“(ख) “कंपनी अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;”;

(ङ) खंड (खक) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“(खक) “डिबेंचर” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (30) के अर्थ के भीतर डिबेंचर अभिप्रेत है;”;

(च) खंड (खख) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“(खख) “डिबेंचर न्यासी” से किसी निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के डिबेंचरों के किसी निर्गम (इश्यू) के संबंध में नियुक्त किया गया न्यासी (ट्रस्टी) अभिप्रेत है;”;

(छ) खंड (ड) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“(ड) “बीमा कंपनी” का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उप-धारा (7क) के अधीन इसके लिए नियत है;”;

(ज) खंड (डक) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“(डक) “निर्गम” (इश्यू) से निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) द्वारा, जनता के लिए या ऐसे निगमित निकाय की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के धारकों (होल्डर्स) के लिए लाया गया डिबेंचरों का प्रस्ताव (ऑफर) अभिप्रेत है और जिसमें उस निगमित निकाय द्वारा लाया गया डिबेंचरों का निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) शामिल है, जो अपनी ऋण प्रतिभूतियाँ (डेट सिक्यूरिटीज़) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना चाहता हो;”;

(झ) खंड (च) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“(च) “मुख्य अधिकारी” (प्रिंसिपल ऑफिसर) से,—

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (51) के अधीन यथा परिभाषित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (प्रबंध-मंडल का मुख्य व्यक्ति / की मैनेजिरियल पर्सोनल) अभिप्रेत है, और जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल होगा, जो निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के प्रबंधन या प्रशासन से जुड़ा हो और जिसे बोर्ड की ओर से ऐसी कोई सूचना (नोटिस) दी गई हो जिसमें उसे उसका मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) बताया गया हो;”;

(ज) खंड (झक) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड (झख) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“(झख) “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] की धारा 2 की उप-धारा (च) के अधीन इसके लिए नियत है।”;

(ii) विनियम 7 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“डिबेंचर न्यासी बनने के लिए पात्रता

7. कोई भी व्यक्ति डिबेंचर न्यासी के रूप में कार्य करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह:—

- (क) वाणिज्यिक क्रियाकलाप (कमर्शियल ऐक्टिविटी) करने वाला कोई अनुसूचित बैंक न हो; या
- (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (72) के अधीन यथा परिभाषित कोई लोक वित्तीय संस्था न हो; या
- (ग) कोई बीमा कंपनी न हो; या
- (घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (11) के अधीन यथा परिभाषित निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) न हो।”

(iii) विनियम 13 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“डिबेंचर न्यासियों के रूप में नियुक्ति से पूर्व बाध्यता

13. कोई भी डिबेंचर न्यासी, जिसे विनियम 8 के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, डिबेंचर के प्रत्येक निर्गम (इश्यू) के संबंध में उस रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि—

- (क) वह डिबेंचरों के निर्गम (इश्यू) के लिए अभिदान सूची (सब्सक्रिप्शन लिस्ट) के खुलने से पहले निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के साथ लिखित करार न कर ले;
- (ख) खंड (क) के अधीन किए जाने वाले करार में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल न कर ले:

(i) डिबेंचरों के आबंटन (अलॉटमेंट) के संबंध में सभी विनियमों (रेग्यूलेशन्स)/कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (उपबंधों), दूसरे विनियामक प्राधिकरणों (रेग्युलेटरी अथॉरिटीज़) के मार्गदर्शक सिद्धांतों (दिशानिर्देशों/गाइडलाइन्स) का पालन [मोचन (रिडेंप्शन) किए जाने तक] किए जाने के संबंध में निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) की ओर से वचन;

(ii) वह समय-सीमा, जिसके भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार या किसी विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) द्वारा निर्धारित किए गए प्रावधानों (जो लागू हों) के अनुसार डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) का सृजन किया जाएगा या करार (एग्रीमेंट) किया जाएगा।”

(iv) विनियम 13क और उसके अधीन खंड (क) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“13क. किसी व्यक्ति को डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) डिबेंचर न्यासी,—

- (i) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) का सहयुक्त (सहयोगी/असोसिएट) हो;
- (ii) कंपनी के शेयरों को धारण (होल्ड) करता हो जिनका फायदा सीधा उसे मिलता हो;
- (iii) कंपनी या उसकी नियंत्री (होलिंग), समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयुक्त (सहयोगी/असोसिएट) कंपनी का संप्रवर्तक (प्रमोटर), निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (प्रबंध-मंडल का मुख्य व्यक्ति/की मैनेजरियल पर्सोनल) या कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी हो;
- (iv) डिबेंचर न्यासी के तौर पर दिए जाने वाले पारिश्रमिक के अलावा, कंपनी की ओर से कोई और धनराशि पाने का हकदार हो;
- (v) कंपनी, या उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या उसकी नियंत्री (होलिंग) या सहयुक्त कंपनी अथवा ऐसी नियंत्री (होलिंग) कंपनी की समनुषंगी (सब्सिडियरी) का ऋणी हो;
- (vi) ने ऋणों (डैट) के मूलधन की रकम [डिबेंचरों द्वारा प्रतिभूत (सिक्वोर्ड)] या उस पर देय ब्याज के संबंध में कोई गारंटी दी हो;
- (vii) का कंपनी के साथ कोई ऐसा धनीय (आर्थिक) संबंध हो, जो ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कुल व्यापारावर्त (टर्नओवर) या उसकी कुल आय के 2% या उससे अधिक का हो, अथवा ₹50 लाख का हो या इससे अधिक रकम (जो निर्धारित की जाए) का हो, इनमें से जो भी कम हो;
- (viii) किसी संप्रवर्तक (प्रमोटर) या किसी ऐसे व्यक्ति का नातेदार (रिश्तेदार) हो, जो कंपनी में निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति/की मैनेजरियल पर्सोनल) के रूप में कार्यरत हो;
- (ix) का किसी अन्य प्रकार से हित-विरोध हो सकता हो:

परंतु यह कि यह अपेक्षा उन निर्गमित (इश्यू किए गए) डिबेंचरों के संबंध में लागू नहीं होगी:

- (i) जहाँ भी निर्गमित (इश्यू किए गए) डिबेंचरों के लिए राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटी दी गई हो।”

(v) विनियम 14 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

**“डिबेंचर न्यासियों की बाध्यता**

**14.** प्रत्येक डिबेंचर न्यासी, अन्य बातों के साथ-साथ, उन न्यास विलेखों (ट्रस्ट डीड) को स्वीकार करेगा, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 और कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में दिए हुए प्ररूप संख्या (फॉर्म नं.) एसएच.12 में निर्धारित बातें शामिल हों।”

(vi) विनियम 15 में,—

(क) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

“(1) प्रत्येक डिबेंचर न्यासी का यह कर्तव्य होगा कि वह —

- (क) इस बात से संतुष्ट हो जाए कि प्रॉस्पेक्टस या प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में ऐसी किसी बात का उल्लेख न हो जो डिबेंचरों के निर्गम (इश्यू) की शर्तों आदि से या न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) से असंगत हो;
- (ख) इस बात से संतुष्ट हो जाए कि न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में उल्लिखित प्रसंविदाएँ (शर्तें आदि) डिबेंचर धारकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें;
- (ग) संबद्ध बोर्ड की बैठक से 7 दिनों के भीतर या संबंधित तिमाही के 45 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, निर्गमकर्ता कंपनी (इश्युअर कंपनी) से स्थिति संबंधी/कार्य-निष्पादन संबंधी आवधिक रिपोर्टें मंगाए;
- (घ) ब्याज के भुगतान या डिबेंचरों के मोचन (रिडेंप्शन) में हुई चूकों (डिफॉल्ट), यदि कोई हों, के संबंध में और उसके लिए न्यासी (ट्रस्टी) द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में डिबेंचर धारकों को तुरंत सूचित करे;
- (ङ) निम्नलिखित की दशा में कंपनी के बोर्ड में नामनिर्देशिती (नामिनी) निदेशक नियुक्त करे:
  - (i) डिबेंचर धारकों को किए जाने वाले ब्याज के भुगतान में लगातार दो बार चूक (डिफॉल्ट) होने की दशा में; या
  - (ii) डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के सृजन में चूक (डिफॉल्ट) होने की दशा में; या
  - (iii) डिबेंचरों के मोचन (रिडेंप्शन) में चूक (डिफॉल्ट) होने की दशा में;
- (च) यह सुनिश्चित करे कि कंपनी डिबेंचरों के निर्गम (इश्यू) की शर्तों आदि या न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) की प्रसंविदाओं का कोई उल्लंघन (भंग) नहीं करती और वह ऐसे मुनासिब कदम उठाए जो ऐसे किसी उल्लंघन (भंग) को सुधारने के लिए जरूरी हों;
- (छ) डिबेंचरों के निर्गम (इश्यू) की शर्तों आदि या न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) की प्रसंविदाओं के किसी उल्लंघन (भंग) की सूचना डिबेंचर धारकों को तुरंत दे;
- (ज) यह सुनिश्चित करे कि डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के सृजन (यदि कोई हो) और डिबेंचर मोचन आरक्षिति (डिबेंचर रिडेंप्शन रिज़र्व) के सृजन से संबंधित शर्तों का पालन किया जा रहा है;

- (झ) यह सुनिश्चित करे कि डिबेंचरों का निर्गम (इश्यू) लाने वाली कंपनी और गारंटी देने वालों (गारंटर), यदि कोई हों, की आस्तियाँ (असेट्स) हमेशा ब्याज और मूलधन की रकम चुकाए जाने के लिए पर्याप्त रहें और ऐसी आस्तियाँ (असेट्स) किन्हीं दूसरे ऋण-धारों (विल्लंगमों/इन्कम्ब्रेन्स) से मुक्त रहें, किंतु उन ऋण-धारों में वे ऋण-भार शामिल नहीं हैं जिनके संबंध में डिबेंचर धारकों द्वारा विशेष रूप से सहमति दे दी गई हो;
- (ञ) ऐसे कार्य करे जो प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के प्रवर्तनीय (इन्फोर्सेबल) हो जाने की दशा में करने जरूरी हों;
- (ट) डिबेंचरों के निर्गम (इश्यू) के जरिए जुटाए गए पैसों (निधियों/फंड्स) के उपयोग के संबंध में रिपोर्टें मंगाए;
- (ठ) डिबेंचर धारकों की बैठक आयोजित करवाने के लिए कदम उठाए, जब भी ऐसी बैठक आयोजित करवाना अपेक्षित हो;
- (ड) यह सुनिश्चित करे कि डिबेंचरों का संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न) या उनका मोचन (रिडेंप्शन) डिबेंचरों के निर्गम (इश्यू) की शर्तों आदि के अनुसार किया गया है;
- (ढ) ऐसे कार्य करे जो डिबेंचर धारकों के हित का संरक्षण करने के लिए जरूरी हों और ऐसे दूसरे सभी कार्य भी करे जो डिबेंचर धारकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जरूरी हों;
- (ण) न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के प्रावधानों के अनुसार न्यास (ट्रस्ट) की संपत्ति को कब्जे में ले ले;
- (त) न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) या कानून के किसी उल्लंघन (भंग) की जानकारी मिलते ही डिबेंचर धारकों के हित का संरक्षण करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए;
- (थ) यह सुनिश्चित कर ले और इस बात से संतुष्ट हो जाए कि,—
- (i) उस मामले में जहाँ आबंटन पत्र जारी कर दिया गया हो और डिबेंचर प्रमाणपत्र ऋण-भार (चार्ज) का रजिस्ट्रीकरण कराने के बाद जारी किया जाना हो, वहाँ डिबेंचर प्रमाणपत्र, कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ ऋण-भार (चार्ज) के रजिस्ट्रीकरण के 30 दिनों के भीतर, निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) द्वारा डिबेंचर धारकों को भिजवा दिए जाएँ;
  - (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 [सेबी (डिबेंचर ट्रस्टीज़) रेग्यूलेशन, 1993], भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 [सेबी (इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डैट सिक्यूरिटीज़) रेग्यूलेशन, 2008], भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन, 2015] तथा बोर्ड द्वारा जारी किन्हीं दूसरे विनियमों (रेग्यूलेशन) के अनुसार, डिबेंचर प्रमाणपत्र डिबेंचर धारकों

को भिजवा दिए जाएँ या डिबेंचर धारकों के डीमैट खातों में डिबेंचर जमा करवा दिए जाएँ;

(iii) डिबेंचरों पर देय व्याज के लिए व्याज वारंट (इंटेरेस्ट वारंट) डिबेंचर धारकों को, नियत तारीखों को या उनसे पहले ही, भिजवा दिए जाएँ;

(iv) डिबेंचर धारकों को वह धनराशि अदा कर दी जाए, जो डिबेंचरों के मोचन (रिडेम्प्शन) की तारीख को उन्हें देय हो;

(द) न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) या किसी कानूनी प्रावधान के किसी उल्लंघन (भंग) की जानकारी मिलते ही बोर्ड को तुरंत सूचित करे:

**स्पष्टीकरण :** डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा डिबेंचर धारकों को दी जाने वाली सूचना (जिसका उल्लेख इन विनियमों में किया गया है) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रेस विज्ञप्ति के जरिए और उसके वेबसाइट पर सूचना (नोटिस) डलवाकर दी जा सकेगी;

(ध) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) द्वारा कंपनी अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015], स्टॉक एक्सचेंज के सूचीबद्धता करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) या न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) या ऋण निर्गम (डैट इश्यू) के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी किन्हीं दूसरे विनियमों (रेग्यूलेशन्स) का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तत्परता बरते;

(न) उस मामले में जहाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) को प्राप्य राशियों (रिसीवेबल्स)/बही ऋणों (बुक डैट) के आधार पर प्रतिभूत (सिक्योर्ड) किया जाता हो, वहाँ निम्नलिखित प्राप्त करेगा,—

(i) तिमाही आधार पर—

(क) निर्गमकर्ता कंपनी (इश्युअर कंपनी) के निदेशक/प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) का प्रमाणपत्र, जिसमें बही ऋणों (बुक डैट्स)/प्राप्य राशियों (रिसीवेबल्स) के मूल्य को प्रमाणित किया गया हो;

(ख) स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र, जिसमें बही ऋणों (बुक डैट्स)/प्राप्य राशियों (रिसीवेबल्स) का मूल्य दिया गया हो।

(ii) वार्षिक आधार पर—

(क) कानूनी लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, जिसमें बही ऋणों (बुक डैट्स) / प्राप्य राशियों (रिसीवेबल्स) का मूल्य दिया गया हो।"

(vii) विनियम 15 में, उप-विनियम (1क) में, खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

"(ग) निर्गमकर्ता (इश्युअर) के कानूनी लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा:

(i) परियोजना (प्रोजेक्ट) की कार्यान्वयन अवधि के दौरान पैसों (निधियों/फंड्स) के उपयोग के संबंध में; और

(ii) कार्यशील पूँजी (वर्किंग कैपिटल) के वित्तपोषण (की फाइनेंसिंग) हेतु निर्गमित (इश्यू किए गए) डिबेंचरों के मामले में, प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर।"

(viii) विनियम 17 में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

"(1) किसी विधि के प्रावधानों (उपबंधों) के अध्यक्षीन, प्रत्येक डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी), डिबेंचरों के मोचन (रिडेंप्शन) की तारीख से कम से कम पाँच वित्तीय वर्षों की अवधि तक, न्यासी के कार्यों (कृत्यों) से संबंधित समुचित लेखा-बहियाँ, रिकॉर्ड और दस्तावेज रखेगा।"

(ix) विनियम 17क में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(4) इस प्रकार नियुक्त किया गया अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 [सेबी (सर्टिफिकेशन ऑफ असोसिएटेड पर्सन्स इन द सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) रेग्यूलेशन्स, 2007] के अनुसार प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) प्राप्त करेगा, या वह प्रमाणीकरण प्राप्त करेगा जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।"

(x) विनियम 19 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

"कि कंपनी अधिनियम, 2013, परिपत्रों (सर्कुलर्स), नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है;"

(xi) विनियम 25 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

**"चूक (व्यतिक्रम / डिफॉल्ट) के मामले में कार्रवाई के लिए दायित्व**

**25. (1) जो डिबेंचर न्यासी -**

- (क) ऐसी किन्हीं शर्तों का पालन करने में असफल रहता है, जिनके अध्यक्षीन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो;
- (ख) अधिनियम या इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है;
- (ग) कंपनी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है;
- (घ) डिबेंचर न्यासी के रूप में अपने क्रियाकलाप (ऐक्टिविटी) से संबंधित कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहता है, जो बोर्ड द्वारा माँगी जाए;
- (ङ) बोर्ड को ऐसी जानकारी देता है, जिसकी कोई महत्वपूर्ण बात मिथ्या या भ्रामक हो;
- (च) बोर्ड की अपेक्षानुसार आवधिक (समय-समय पर) विवरणियाँ (रिटर्न) या रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं करता है;
- (छ) बोर्ड द्वारा की जा रही किसी जाँच, किए जा रहे किसी निरीक्षण या अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) में सहयोग नहीं करता है;
- (ज) निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) की शिकायतों का निवारण करने में असफल रहता है या उस संबंध में बोर्ड को संतोषजनक उत्तर देने में असफल रहता है,



उस पर कार्यवाही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] के अनुसार की जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) में दी हुई कोई भी बात अधिनियम की धारा 11, 11ख (11बी), 11घ (11डी), धारा 12 की उप-धारा (3) या धारा 24 या अध्याय VI के अधीन या तत्समय प्रवृत्त (लागू) किसी अन्य विधि के अधीन निदेश जारी करने या उपाय करने की बोर्ड की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।"

(xii) अनुसूची IV का लोप हो जाएगा।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./106/17 (69 जैडबी)]

#### पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, सं. सेबी/एलई/12/93, 29 दिसम्बर 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 तत्पश्चात्:
  - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं. 939(अ), द्वारा 28 नवम्बर 1995
  - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 16(अ), द्वारा 5 जनवरी 1998
  - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 795(अ), द्वारा 30 सितम्बर 1999
  - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 135(अ), द्वारा 17 फरवरी 2000
  - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 743(अ), द्वारा 8 अगस्त 2000
  - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278(अ), द्वारा 28 मार्च 2000
  - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा 29 मई 2001
  - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का. आ. सं. 1045(अ), द्वारा 27 सितम्बर 2002
  - (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 763(अ), द्वारा 4 जुलाई 2003
  - (ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा 10 मार्च 2004

- (ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1451(अ), द्वारा 7 सितम्बर 2006
- (ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा 26 मई 2008
- (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कुछ मध्यवर्तियों [इंटरमीडियरीज़] के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा 13 अप्रैल, 2011
- (ढ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2011, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/13/21222, द्वारा 5 जुलाई 2011
- (ण) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/30/37715, द्वारा 14 दिसम्बर 2011
- (त) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा 23 मई 2014
- (थ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा 8 दिसम्बर, 2016
- (द) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा 6 मार्च, 2017 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित] को संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 13th June, 2017

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEBENTURE TRUSTEES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

**No.SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/011.**—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby, makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993,—
  - (i) in regulation 2, —
    - (a) for clause (aa) the following shall be substituted, namely,—

“associate” shall mean any entity which is an associate under sub-section (6) of section 2 of the Companies Act, 2013 or under the applicable accounting standards and shall include a

person whose director, is also a director, of the debenture trustee or the body corporate, as the case may be.”;

- (b) for clause (ab) the following shall be substituted, namely,—  
 “body corporate” shall have the meaning assigned to it in or under sub-section (11) of section 2 of the Companies Act, 2013 and for the purpose of these regulations, includes a public financial institution as defined under sub-section (72) of section 2 of the Companies Act, 2013, a non-banking financial company, public sector undertaking established under any Central or State enactment which has its debt securities listed or which seeks to list its debt securities on a recognized stock exchange in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, or any other issuer of debt securities in accordance with any Regulations issued by the Board.”;
- (c) in clause (ae), for clause (i) the following shall be substituted, namely,—  
 “if its shares are listed on any recognised stock exchange, change in control as per the provisions of regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;”;
- (d) for clause (b) the following shall be substituted, namely,—  
 “ “Companies Act” means the Companies Act, 2013 (Act 18 of 2013);”;
- (e) for clause (ba) the following shall be substituted, namely,—  
 “debenture” means a debenture within the meaning of sub-section (30) of section 2 of the Companies Act, 2013;”;
- (f) for clause (bb) the following shall be substituted, namely—  
 “debenture trustee” means a trustee appointed in respect of any issue of debentures of a body corporate;”;
- (g) for clause (e) the following shall be substituted, namely,—  
 “insurance company” has the same meaning assigned to it under sub-section (7A) of section 2 of the Insurance Act, 1938;”;
- (h) for clause (ea) the following shall be substituted, namely—  
 “issue” means an offer of debentures by a body corporate, to the public, or the holders of securities of such body corporate and includes a private placement of debentures made by a body corporate, which seeks to list its debt securities on a recognized stock exchange;”;
- (i) for clause (f) the following shall be substituted, namely—  
 “principal officer” means,—  
 a key managerial personnel as defined under sub section (51) of section 2 of the Companies Act, 2013, and shall include any person connected with the management or administration of the body corporate upon whom the Board has served notice of its intention of treating him as the principal officer thereof;”;
- (j) after clause (ia) the following new clause (ib) shall be inserted, namely,—  
 “(ib) “recognised stock exchange” shall have the same meaning assigned to it under sub-section (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.”;
- (ii) for regulation 7, the following shall be substituted, namely,—

**“Eligibility for being debenture trustee.**

7. No person shall be entitled to act as a debenture trustee unless it is :—

- (a) a scheduled bank carrying on commercial activity; or
- (b) a public financial institution as defined sub-section (72) of section 2 of the Companies Act, 2013; or

(c) an insurance company; or

(d) body corporate as defined under sub-section (11) of section 2 of the Companies Act, 2013.”

(iii) in regulation 13, in clause (b),-

(a) for sub-clause (i) the following shall be substituted, namely,-

“(i) an undertaking by the body corporate to comply with all regulations/provisions of Companies Act, 2013, guidelines of other regulatory authorities in respect of allotment of debentures till redemption;”

(b) for sub-clause (ii) the following shall be substituted, namely,-

“(ii) the time limit within which the security for the debentures shall be created or the agreement shall be executed in accordance with the Companies Act, 2013 or provisions as prescribed by any regulatory authority as applicable.”

(iv) for regulation 13A and clause (a) thereunder, the following shall be substituted, namely,-

“**13A.** A person shall not be appointed as a debenture trustee, in case-

(a) the debenture trustee,-

(i) is an associate of the body corporate;

(ii) beneficially holds shares in the company;

(iii) is a promoter, director or key managerial personnel or any other officer or an employee of the company or its holding, subsidiary or associate company;

(iv) is beneficially entitled to moneys which are to be paid by the company otherwise than as remuneration payable to the debenture trustee;

(v) is indebted to the company, or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company;

(vi) has furnished any guarantee in respect of the principal debts secured by the debentures or interest thereon;

(vii) has any pecuniary relationship with the company amounting to 2% or more of its gross turnover or total income or ₹50 lakh or such higher amount as may be prescribed, whichever is lower, during the two immediately preceding financial years or during the current financial year;

(viii) is relative of any promoter or any person who is in the employment of the company as a director or key managerial personnel;

(ix) is likely to have conflict of interest in any other manner:

Provided that this requirement shall not be applicable in respect of debentures issued:

(i) wherever there is guarantee by the state/central government for the debentures issued.”

(v) for regulation 14 the following shall be substituted, namely,-

“**Obligation of the debenture trustees.**

**14.** Every debenture trustee shall amongst other matters, accept the trust deeds which shall contain the matters as specified in section 71 of Companies Act, 2013 and Form No. SH.12 specified under the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014.”

(vi) in regulation 15, —

(a) for sub-regulation (1) the following shall be substituted, namely, —

“(1) It shall be the duty of every debenture trustee to-

- (a) satisfy itself that the prospectus or letter of offer does not contain any matter which is inconsistent with the terms of the issue of debentures or with the trust deed;
- (b) satisfy itself that the covenants in the trust deed are not prejudicial to the interest of the debenture holders;
- (c) call for periodical status/ performance reports from the issuer company within 7 days of the relevant board meeting or within 45 days of the respective quarter whichever is earlier;
- (d) communicate promptly to the debenture holders defaults, if any, with regard to payment of interest or redemption of debentures and action taken by the trustee therefor;
- (e) appoint a nominee director on the Board of the company in the event of:
  - (i) two consecutive defaults in payment of interest to the debenture holders; or
  - (ii) default in creation of security for debentures; or
  - (iii) default in redemption of debentures.
- (f) ensure that the company does not commit any breach of the terms of issue of debentures or covenants of the trust deed and take such reasonable steps as may be necessary to remedy any such breach;
- (g) inform the debenture holders immediately of any breach of the terms of issue of debentures or covenants of the trust deed;
- (h) ensure the implementation of the conditions regarding creation of security for the debentures, if any, and debenture redemption reserve;
- (i) ensure that the assets of the company issuing debentures and of the guarantors, if any, are sufficient to discharge the interest and principal amount at all times and that such assets are free from any other encumbrances except those which are specifically agreed to by the debenture holders;
- (j) do such acts as are necessary in the event the security becomes enforceable;
- (k) call for reports on the utilization of funds raised by the issue of debentures;
- (l) take steps to convene a meeting of the holders of debentures as and when such meeting is required to be held;
- (m) ensure that the debentures have been converted or redeemed in accordance with the terms of the issue of debentures;
- (n) perform such acts as are necessary for the protection of the interest of the debenture holders and do all other acts as are necessary in order to resolve the grievances of the debenture holders;
- (o) take possession of trust property in accordance with the provisions of the trust deed;
- (p) to take appropriate measures for protecting the interest of the debenture holders as soon as any breach of the trust deed or law comes to his notice;
- (q) ascertain and satisfy itself that,-
  - (i) in case where the allotment letter has been issued and debenture certificate is to be issued after registration of charge, the debenture certificates have been dispatched by the body corporate to the debenture holders within 30 days of the registration of the charge with the Registrar of Companies;

- (ii) debenture certificates have been dispatched to the debenture holders or debentures have been credited in the demat accounts of the debenture holders in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations 1993, Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations 2008, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and any other regulations issued by the Board;
- (iii) interest warrants for interest due on the debentures have been dispatched to the debenture holders on or before the due dates;
- (iv) debenture holders have been paid the monies due to them on the date of redemption of the debentures;
- (r) inform the Board immediately of any breach of trust deed or provision of any law, which comes to the knowledge of the trustee.

Explanation: The communication to the debenture holders by the debenture trustee as mentioned in these regulations may be made by electronic media, press-release and placing notice on its website;

- (s) exercise due diligence to ensure compliance by the body corporate, with the provisions of the Companies Act, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement), Regulations, 2015, the listing agreement of the stock exchange or the trust deed or any other regulations issued by the Board pertaining to debt issue;
- (t) In case where listed debt securities are secured by way of receivables/ book debts it shall obtain the following,-
  - (i) On Quarterly basis-
    - (a) Certificate from the Director / Managing Director of the issuer company certifying the value of the book debts / receivables;
    - (b) Certificate from an independent chartered accountant giving the value of book debts / receivables.
  - (ii) On Yearly basis-
    - (a) Certificate from the statutory auditor giving the value of book debts / receivables.

- (vii) in regulation 15, in sub-regulation (1A), clause (c) shall be substituted with the following, namely,-

“(c) obtain a certificate from the issuer's Statutory Auditor:

- (i) in respect of utilisation of funds during the implementation period of the project; and
- (ii) in the case of debentures issued for financing working capital, at the end of each accounting year.”

- (viii) in regulation 17, for sub-regulation (1) the following shall be substituted, namely,—

“(1) Subject to the provisions of any law every debenture trustee shall keep and maintain proper books of account, records and documents, relating to the trusteeship functions for a period of not less than five financial years from the date of redemption of debentures.”

- (ix) in regulation 17A, after sub-regulation (3) the following new sub-regulation shall be inserted, namely,—

“(4) The Compliance Officer so appointed shall obtain certification in terms of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 or as may be specified by the Board.”

- (x) in regulation 19, in sub-regulation (2), for clause (b), the following shall be substituted, namely,—  
“(b) that the provisions of the Companies Act, 2013, Circulars, rules and regulations are being complied with;”
- (xi) for regulation 25, the following shall be substituted, namely,—

**“Liability for action in case of default.**

25. (1) A Debenture Trustee which-

- (a) fails to comply with any conditions subject to which certificate has been granted;
- (b) contravenes any of the provisions of the Act or these regulations;
- (c) contravenes the provisions of the Companies Act or the rules made there under;
- (d) fails to furnish any information relating to its activity as a Debenture Trustee as required by the Board;
- (e) furnishes to the Board information which is false or misleading in any material particular;
- (f) does not submit periodic returns or reports as required by the Board;
- (g) does not co-operate in any enquiry, inspection or investigation conducted by the Board;
- (h) fails to resolve the complaints of investors or fails to give a satisfactory reply to the Board in this behalf;

shall be dealt with in the manner provided under the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

(2) Nothing contained in sub-regulation (1) shall prejudice the powers of the Board to issue directions or measures under sections 11, 11B, 11D, sub-section (3) of section 12 or section 24 or Chapter VIA of the Act or under any other law for the time being in force.”

- (xii) Schedule IV shall be omitted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.- III/4/Exty./106/17 (69ZB)]

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide S.O. No. 780(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993, were subsequently amended on:
  - (a) November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No.939 (E).
  - (b) January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.16(E).
  - (c) September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.795(E).
  - (d) February 17, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 135(E).
  - (e) August 8, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 743(E).
  - (f) March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278(E).
  - (g) May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).

- (h) September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 *vide* S.O. No. 1045(E).
- (i) July 4, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2003 *vide* S.O.No. 763(E).
- (j) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 *vide* S.O. No. 398(E).
- (k) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2006 *vide* S.O No. 1451(E).
- (l) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538.
- (m) April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011-12/03/12650.
- (n) July 05, 2011 by the Securities and Exchange Board Of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2011 No. LAD-NRO/GN/2011-12/13/21222.
- (o) December 14, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Second Amendment) Regulations, 2011 No. LAD-NRO/GN/2011-12/30/37715.
- (p) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (q) December 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 *vide* Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/023.
- (r) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/038.